"कापार्ट" द्वारा सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र पथराही, बिहार को जारी की गई धनराशि

7368. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबनी जिले में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही झंझारपुर (आर०एस०) को इसकी योजनाओं के लिए विगत छः महीनों में "कापार्ट" द्वारा स्वीकृत की गई एवं जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी योजनाओं के नाम, जारी की गई राशि की तिथियां तथा इस संबंध में की गई प्रगति का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या "कापार्ट" द्वारा इस संगठन के विरुद्ध जांच समिति गठित की गई है;

(घ) जांच समिति के सदस्यों का ब्यौरा और जांच के बिन्दु क्या हैं; और

(ङ) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) और (ख) सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही, झंझारपुर, जिला मधुबनी, बिहार को पिछले छः महीनों के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए कापार्ट द्वारा मंजूर की गई राशि तथा रिलीज की गई राशि के ब्यौरे तथा मंजूर परियोजनाओं की प्रगति निम्नलिखित है:—

क्रमांक	योजना का नाम	तारीख सहित मंजूर की गई राशि	तारीख सहित रिलीज की गई राशि	परियोजना की प्रगति
1.	सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण	8,66,000 रू० (8.8.94)	4,91,000 रु० (11.10.94) 3,75,000 रु० (14.12.94)	परियोजना का कार्यान्वयन संतोषजनक रहा।
2.	हैंड पम्पों को लगाना	5,44,500 रु० (31.10.94)	शून्य	निधियां अभी रिलीज की जानी हैं।
	कुल:	14,10,500 रु०	8,66,000 रु०	

(ग) जी हां।

(घ) पूछताछ समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. गया के श्री टी० सरण
2. दिल्ली के श्री एस० वेंकटरमण
3. पटना के श्री आर० एल० दीवान

पूछताछ समिति निम्नलिखित पहलुओं को देखेगी:

(1) सामान्य रूप से समिति के कार्यकरण और समिति पंजीकरण अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करना।

(2) समिति के मामलों से संबंधित रिकार्डों का रख-रखाव तथा बैंक खातों के संचालन सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय सहायता।

(3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वैच्छता कार्यक्रम दोनों के अन्तर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन तथा क्षेत्र में लोगों को प्राप्त होने वाले लाभ।

(4) सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं उन पर निधियों का उपयोग आदि।

(ङ) जांच समिति से 31.7.1995 तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए निवेदन किया गया है।

Backward Districts of Gujarat benefited under Special Employment Generation Scheme

7369. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all the backward districts of Gujarat are likely to